

उत्तराखण्ड शासन
राजस्व अनुभाग-2
संख्या: XVIII(II) / 2013-2(01) / 2010
देहरादून: दिनांक: २४ जुलाई, 2013

कार्यालय ज्ञाप

जनपद उधमसिंह नगर में पुनर्वास योजना के अधीन विस्थापित होकर आये परिवारों को आवंटित भूमि पर काबिज कब्जा धारकों को भूमिधरी अधिकार दिये जाने विषयक प्रस्ताव पर शासन द्वारा विचार किया गया। सम्यक विचारोपरान्त इस विषय के विधिक, वित्तीय, व्यावहारिक एवं अन्य प्रासंगिक पहलुओं पर विचार करके अपनी संस्तुतियां दिये जाने हेतु मंत्रिमण्डल की उप समिति का निम्नवत गठन किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. मा० राजस्व मंत्री	-	अध्यक्ष
2. मा० कृषि मंत्री	-	सदस्य
3. मा० पंचायती राज मंत्री	-	सदस्य
4. मा० समाज कल्याण मंत्री	-	सदस्य
5. सचिव, राजस्व विभाग	-	सदस्य सचिव

उक्त समिति द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के भूमिहीनों को जारी किये गये पट्टों के विनियमितीकरण तथा राज्य में वर्ग 3 एवं 4 के भूमि के विनियमितीकरण के संबंध में उत्पन्न हुई विसंगतियों के निराकरण तथा इन विषयों के विधिक, वित्तीय, व्यावहारिक एवं अन्य प्रासंगिक पहलुओं पर भी विचार करके अपनी संस्तुतियां शीघ्रातिशीघ्र मंत्रिमण्डल के विचारार्थ प्रस्तुत की जायेगी।

(सुभाष कुमार)
मुख्य सचिव।

पृष्ठ संख्या ३४। / समिति की विवरण / 2013

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मा० राजस्व मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मा० सदस्यगण, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
6. जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर।
7. निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सुभाष कुमार
(भास्करानन्द)
सचिव।